वर्ष के बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उपर्युक्त रेल लाइनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या क्षेत्रीय मांग को देखते हुए सरकार इन्दौर-महू-पीतमपुर रेल लाइन (जिसका बड़ी लाइन में परिवर्तन करने सहित) का निर्माण कार्य आरंभ करने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । प्राक्कलित लागत 297.14 करोड़ रुपए है । चालू वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान 1 करोड़ रुपए है । देवास-मक्सी खंड पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और प्रगति 19.5% है ।

(ख) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश में बड़ी रेल लाइनें

3047. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत बड़ी रेल लाइनें थीं ;

(ख) गत वर्ष कितने प्रतिशत बड़ी लाइन बिछाने का प्रस्ताव था तथा उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्र इससे संबंधित थे ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-91 को (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) उत्तर प्रदेश में बड़ी लाइन की मार्ग लंबाई भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन की मार्ग लंबाई का 17.81% थी और उस राज्य की कुल मार्ग लम्बाई का 69.61% थी ।

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 9% नई लाइन खोलने का लक्ष्य रखा गया है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह लाइन रामपुर बिलासपुर (27.50कि.मी.) थी, जो रामपुर-न्यू हलद्वानी परियोजना का एक हिस्सा थी, जिसके लिए वर्ष 1991-92 के दौरान 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी ।

उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनों का बिछाया जाना

3048. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) उस राज्य में बिछाई जा रही अन्य रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव फर्रुखाबाद से हरदोई/सांडिला तक नई लाइन के निर्माण के लिए था, जिस पर भारी निवेश अपेक्षित होने और प्रस्तावित लाइन अलाभप्रद प्रकृति की होने के कारण विचार नहीं किया जा सका ।